चमकीली दुनिया का 'काला-बाजार'

पायरेसी के मामले में भारत सबसे बदनाम है। फिल्म, रिलीज होने के कुछ घंटों में ही डीवीडी और सीडी बाजार में आ जाती हैं। फिल्मों की यह नकल अकसर गांवों और छोटे शहरों में ज्यादा पसंद की जाती है। टॉकीज के परदे के सामने कैमरा लगा कर तुरत-फुरत नकल का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है।

चेन्नै से गौतमन भास्करन

वीडियो चोरी के दौर में सलमान खान, शाहरुख खान या रजनीकांत हों या फिर अजीत... सभी की फिल्में इससे अछूती नहीं रही हैं। चेन्नई में अकसर ऑटो रिक्शा ड्रायवर हों या नौकरानी, उन्हें फिल्म रिलीज के पहले ही ऐसी फिल्मों के बारे में बातें करते देखा जा सकता है। हालांकि, इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि फिल्म पायरेसी का यह कारोबार कितने का है और फिल्मों को इससे कितना नुकसान हुआ, फिर भी अनुमान है कि विश्व में लगभग पच्चीस अरब डॉलर का कारोबार होता है।

यह अकेला ऐसा उद्योग है, जो हजारों लोगों का रोजगार बन चुका है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय फिल्म उद्योग में सालाना कई भाषाओं में लगभग बारह सौ फिल्में बनती हैं। इनका चौदह फीसदी मुनाफा पायरेसी कारोबार की भेंट चढ़ जाता है। हालांकि, इसमें इंटरनेट के जरिये डाउन लोड से हुए नुकसान का आंकड़ा शामिल नहीं है। यदि विदेशी फिल्मों की पायरेसी भी इसमें जोड़ दी जाए, तो यह काला कारोबार बहुत ज्यादा का हो सकता है।

भारतीय सिनेमा में पायरेसी का दायरा सीमित है। कुछ साल पहले आधुनिक जापानी फिल्मों पर शोध के समय पता चला था कि भारत में फिल्म रिलीज होने के एक-दो दिन पहले हिंदी या तमिल फिल्मों की पायरेटेड डीवीडी टोक्यो में खुलेआम बिक रही थीं। शक किया जा सकता है कि फिल्म से जुड़े टेक्नीशियन इसमें शामिल हो सकते हैं। माराकश फिल्म समारोह के दौरान पता चला कि वहां बॉलीवुड की नई हिट फिल्मों की डीवीडी तीन डॉलर तक बाजार में खुलेआम मिल रही हैं। भारत में, खासकर चेन्नई में चल रहे 'बर्मा बाजार' में ताजा बॉलीवुड फिल्मों की नकल धड़ल्ले से मिल जाती है। इनमें इंग्लिश, हिंदी और दूसरी फिल्में भी शामिल हैं। विदेशी फिल्मों की सीडी भी केवल चालीस रुपए में यहां मिल जाती हैं। इसकी तुलना में किसी स्टोर से ऐसी सीडी खरीदना दस गुना तक महंगा पड़ता है, बशर्ते पसंद की फिल्म वहां हो।

यहां बंगाली और उड़िया फिल्मों की नकल मुश्किल से मिलती है, लेकिन चेन्नई और मुंबई में मिल जाती है। हकीकत यह है कि अच्छी अमेरिकी या ब्रिटिश फिल्मों को भारतीय सिनेमा घरों में मुश्किल से जगह मिल पाती है। वुडी एलन की फिल्म को तो पिछले दिनों भारतीय सिनेमा घरों में जगह ही नहीं मिली। कारण था... शराब की चेतावनी दिखाने का। भारतीय फिल्मों में नग्नता मंजूर नहीं की जाती, लेकिन खूनी हिंसा को जगह मिल जाती है। फ्रेंच डायरेक्टर फ्रेंकिस ओजोन की फिल्म में स्वीमिंग पूल का सीन था, लेकिन भारत में इसे लगभग आधा घंटे कट करके दिखाया गया। सोचा जा सकता है कि बाकी फिल्म में क्या बचा होगा कि फिल्म ही 103 मिनट की थी। भारतीय सेंसर बोर्ड शायद सोचता है कि लुडीवाइन सेगनेर (फ्रेंच अभिनेत्री) हमारी नैतिकता के लिए अच्छी नहीं हैं। सरकार, सिनेमा कारोबारियों से कह रही है कि अमेरिका जैसा रेटिंग सिस्टम शुरू किया जाए, जहां फिल्म को सेंसर करने की बजाय अलग-अलग उम्र वालों के लिए उसे नंबर मिलें। श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी रेटिंग सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की है। इसके बाद कई विदेशी फिल्मकार अपनी फिल्मों को भारत भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि, इनमें भी कुछ ही बड़े नाम हैं। फिल्म की रिलीज के पहले चोरी का पता लगाने के लिए यशराज, यू-टीवी, इरोज इंटरनेशनल, शेमारू और मोजर वियर जैसे बड़े घरानों ने दिसंबर 2008 में मिल कर पायरेसी रोकने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

कुछ महीने पहले तमिल फिल्मकारों ने तय किया था कि तीन महीने के लिए तमाम फिल्मों की रिलीज रोक दें, तो पायरेसी बाजार सूख जाएगा, लेकिन वहां परेशानी यह है कि हर शुक्रवार तीन फिल्में रिलीज होती हैं। ऐसे में फिल्मों पर रोक ठीक नहीं है कि वैसे भी देश में सिनेमा घर कम होते जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जापान और कुछ दूसरे देशों की तरह फिल्मों की रिलीज के पहले वीडियो-अधिकार वितरकों को दे दिए जाएं, जो खुद अपनी फिल्मों के वीडियो बना कर मार्केट में उतारें। इससे पायरेसी पर रोक लग सकती है। कुछ समय पहले कमल हासन अपनी फिल्म 'विश्व रूपम' को सिनेमा घरों के साथ टीवी पर भी रिलीज करना चाहते थे, लेकिन वितरकों ने विरोध किया। सरकार को भी चाहिए कि सेंसरशिप को रेटिंग प्रणाली में बदल दिया जाए, जिससे विश्व सिनेमा में भारत को खास मदद मिल सके। वैसे, भारतीय फिल्में देश भर में आसानी से मिलना चाहिए। उनका अनुवाद अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी हो, ताकि लोगों को मदद मिल सके।